नईदुनिया

सीसीपीए ने सेवा शुल्क वापस न करने पर दिल्ली के पांच रेस्तरां पर की कार्रवाई

नई दिल्ली

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिल्ली के पांच रेस्तरां मखना डेली, जेरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ कार्रवाई की है। इन रेस्तरां ने दिल्ली होई कोर्ट के आदेश के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क की वापस नहीं किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इनको सेवा शुल्क की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।

सीसीपीए ने 04 जुलाई 2022 को होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क को स्वत: या डिफ़ॉल्ट रूप से बिल में नहीं जोड़ेगा। साथ ही, सेवा शुल्क का संग्रह किसी अन्य नाम से नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सेवा शुल्क वैकल्पिक है और यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीपीए के सेवा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा। इसके बाद, सीसीपीए को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में कहा गया कि कुछ रेस्तरां बिना पूर्व सहमति के अनिवार्य सेवा शुल्क लगा रहे हैं। सीसीपीए का गठन उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और गलत विज्ञापनों के मामलों को विनियमित करने के लिए किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

डायमंड पावर इंफ्रा को 230 करोड़ के दो ठेके मिले

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एकल-स्थान विद्युत केबल और कंडक्टर विनिर्माता कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीपीआईएल) को बिजली केबल की आपूर्ति के लिए 230 करोड़ रुपये से अधिक के दो ठेके मिले हैं। डीपीआईएल की ओर से जारी बयान के अनुसार कंपनी को दक्षिण गुजरात विज कंपनी के तहत परियोजना के लिए राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड से 1,50,98,65,000 रुपये और बिजली केबल की आपूर्ति के लिए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 79,27,80,051 रुपये का ठेका मिला है।

आरबीआई मई में 1.25 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई में 1.25 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदने की योजना बनाई है। इस पहल में, 50,000 करोड़ रुपये की किस्त 6 मई को जारी की जाएगी और आगे की तीन किस्तें 9, 15 और 19 मई को जारी की जाएंगी। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी इसके साथ ही, एक अन्य विकल्प चरखी दाधी जेनसोल इंजीनियरिंग क्षेत्र में संकट का सामना कर रही है। ईडी ने जेनसोल के परिसरों में छापा मारा और कई दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्डों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर मार्च, 2025 में गिरकर तीन फीसदी रही। इससे इंडस्ट्रियल उत्पादन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने आंकड़े संशोधित करके इसे सुधारने का प्रयास किया है। आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर मार्च में तीन फीसदी रह गई है, जबकि खनन की वृद्धि दर 0.4 फीसदी और बिजली की 6.3 फीसदी रही। इससे इंडस्ट्रीज की स्थिरता में सुधार के लिए चुनौती है।

पेट्रोल-डीजल 1 मई से हो सकता है 1.30 रुपए महंगा केरोसिन की कीमत भी बढ़ सकती है 1.35 रुपए

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे घरेलू बाजार भी प्रभावित हो रहा है। इसी की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते दिनों कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 मई से पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ सकते हैं। इस संबंध में अधिकारिक तौर पर बुधवार को अधिसूचना जारी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल-डीजल के दाम में 30 अप्रैल रात 12 बजे के बाद से 1.30 रुपए बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं केरोसिन की कीमत भी 1.35 रुपए बढ़ सकते हैं। बता दें कि हाल ही में यहां की सरकार ने पेट्रोल पर लेवी 8.02 रुपये बढ़ाकर 78.02 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 7.01 रुपए बढ़ा दी थी। हालांकि इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ा। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत 65.52 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 61.87 डॉलर प्रति बैरल पर बनी हुई है।

एडब्ल्यूएल एग्री कारोबार का मुनाफा बढ़कर 191 करोड़

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का मुनाफा 22 प्रतिशत बढ़कर 190.66 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में मुनाफा 156.75 करोड़ रुपये रहा था। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जनवरी-मार्च 2025 में कुल आय बढ़कर 18,291.63 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13,327.05 करोड़ रुपये थी। समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में मुनाफा बढ़कर 1,225.81 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 147.99 करोड़ रुपये था। कुल आय 2024-25 में बढ़कर 63,910.28 करोड़ रुपये हो गई, जो 2023-24 51,518.71 करोड़ रुपये थी। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड फॉर्चयून ब्रांड के तहत खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य उत्पाद बेचती है।

आईफोन 17 की लांचिंग पर मंडरा रहे संकट के बादल, चीन से आयात में देरी बनी बड़ी चुनौती

नई दिल्ली

चीन से आईफोन बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी के आयात की अनुमति में लगातार हो रही देरी ने चिंता बढ़ा दी है। अगर यह देरी जारी रहती है, तो न केवल अपकमिंग आईफोन 17 के लॉन्च पर असर पड़ सकता है, बल्कि भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को दोगुना करने की एप्पल की संभावित योजना भी प्रभावित हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य था कि भारत से उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका में आईफोन की मांग को पूरा किया जाए, ताकि चीन पर लगाए गए भारी आयात शुल्क से बचा जा सके। चीन से आयात को लेकर मंजूरी में देरी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरंग निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ड्रिलिंग मशीनों और सोलर एनर्जी से जुड़ी मशीनों सहित अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार देशभर में सुरंगों के निर्माण पर आक्रामक रूप से काम कर रही है। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के टॉप सूत्र ने बताया कि आम तौर पर एप्पल इंक हर साल एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करता है, जबकि बाकी कंपनियां कम से कम दो मॉडल लॉन्च करती हैं। भारत में नए मॉडल असेंबल करने के लिए बड़ी मात्रा में नई आयातित मशीनों को रेट्रोफिट करना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अब लगातार देरी हो रही है, जो नए मॉडल के लॉन्च को प्रभावित कर सकती है। यह भी आशंका है कि मोबाइल असेंबली के लिए चीन से सेकंडहैंड मशीनरी के आयात जो कि वहां से भारत में उत्पादन क्षमता शिफ्ट करने का हिस्सा है, पर भी सख्ती बढ़ सकती है।

एथर एनर्जी को पहले दिन सिर्फ 16 फीसदी मिला सब्सक्रिप्शन

नई दिल्ली (ईएमएस)। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के पहले दिन निवेशकों से सुस्त रिस्पांस मिला। बाजार में तेजी के बावजूद पब्लिक इश्यू को पहले दिन केवल 16 फीसदी सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए 28 अप्रैल को खुला और 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2,981.06 करोड़ के आईपीओ को पहले दिन कुल 86,09,406 इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। जबकि बिक्री के लिए 5,33,63,160 शेयर रखे गए हैं। आईपीओ सब्सक्राइब के लिए 30 अप्रैल तक खुला रहेगा इस आधार पर पहले दिन की कुल सब्सक्रिप्शन दर 16 प्रतिशत रही। कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा में सबसे अधिक भागीदारी देखी गई। इसमें 1.78 गुना बुकिंग हुई। रिटेल निवेशकों ने अपने लिए आरक्षित श्रेणी में 63 प्रतिशत, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने 16 प्रतिशत और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपने लिए रिजर्व 2,89,27,363 के मुकाबले केवल 5,060 बोलियां लगाईं। एथर एनर्जी आईपीओ ग्रे मार्केट में सपाट रिस्पांस दे रहा है। अनौपचारिक बाजार गतिविधियों पर नजर रखने वाले सूत्रों के अनुसार, कंपनी के नॉन लिस्टेड शेयर मंगलवार को ग्रे मार्केट में 322 रुपये पर कारोबार कर रहे है। यह प्राइस बैंड के अपर एंड 321 रुपये 1 रुपये के प्रीमियम को दर्शाते है।

इंफोसिस में 195 और प्रशिक्षुओं को निकाल बाहर किया

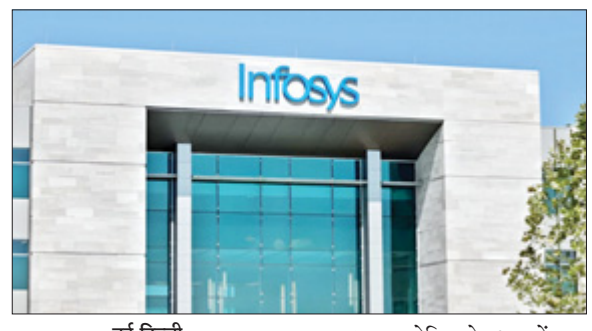

नई दिल्ली

भारत की दूसरे नंबर की आईटी सर्विस प्रोवाइडर फर्म इन्फोसिस ने आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) में खराब प्रदर्शन वाले 195 और प्रशिक्षुओं को कंपनी से बाहर कर दिया। कंपनी की ओर से भेजे गए ईमेल में यह जानकारी सामने आई है। प्रशिक्षुओं को निकालने का यह तीसरा दौर है। पहला दौर फरवरी में हुआ था जब 320 प्रशिक्षुओं को निकाल दिया था। दूसरा दौर इस महीने की शुरुआत में हुआ था, जिसमें 240 प्रशिक्षुओं को निकाला गया था। इन्फोसिस ने 2025 में कुल 15,000 प्रशिक्षुओं को काम पर रखा। प्रभावित प्रशिक्षुओं को 2022 में काम पर रखा गया था, और अक्टूबर 2024 में उन्हें शामिल किया गया था। इन्फोसिस की छंटनी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी और उद्योग एक अनिश्चित मैक्रो माहौल से गुजर रहे हैं। कंपनी ने साल 26 के लिए 0-3 फीसदी के दायरे में रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह वित्त वर्ष 26 के लिए लगभग 20,000 फ्रेशर्स को काम पर रखेगी।

ग्रीनप्लाई का चौथी तिमाही में मुनाफा घटकर हुआ 16.6 करोड़

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्लाईवुड उद्योग की अग्रणी कंपनियों में से एक ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही का मुनाफा 41.45 प्रतिशत घटकर 16.60 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 28.36 करोड़ रुपये रहा था। ग्रीनप्लाई ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जनवरी-मार्च 2025 में कंपनी की परिचालन आय 8.16 प्रतिशत बढ़कर 648.77 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले यह 599.78 करोड़ रुपये रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में मुनाफा 28.36 करोड़ रुपये रहा था कंपनी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण बाजार परिदृश्य में चौथी तिमाही के लिए प्लाईवुड व्यवसाय में वृद्धि संतोषजनक रही। उच्च ब्रांड प्रचार व्यय के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में मार्जिन सुधार के साथ 9.2 प्रतिशत हो गया। समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में मुनाफा 31.12 प्रतिशत बढ़कर 91.72 करोड़ रुपये हो गया। एकीकृत राजस्व 14.11 प्रतिशत बढ़कर 2,487.58 करोड़ रुपये रहा।

मारुति सुजुकी के चौथी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे

देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चौथी तिमाही के परिणाम मिले-जुले रहे। कंपनी का राजस्व में तो इजाफा हुआ, लेकिन एबिड्टा मार्जिन अनुमान से कम रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी का वॉल्यूम 3.5 फीसदी और रियलाइजेशन 2.7 फीसदी बढ़ा। कंपनी की नेट सेल्स सालाना आधार पर 6.4 फीसदी बढ़ी। कंपनी का निर्यात सालाना आधार पर 8.1 फीसदी अधिक रहा कंपनी का निर्यात सालाना आधार पर 8.1 फीसदी अधिक रहा। एबिडिटा मार्जिन में साल दर साल आधार पर 173 आधार अंकों की गिरावट आई। लगातार चौथे साल मारुति सुजुकी अच्छी निर्यातकबनी रही है। भारत के कुल पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपोर्ट में मारुति की हिस्सेदारी करीब 43 फीसदी पहुंच गई है।

डीबीआई बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़कर हुआ 2,051 करोड़

बैंक का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में मुनाफा 1,628 करोड़ रहा था

नई दिल्ली

आईडीबीआई बैंक का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 2,051 करोड़ रुपए रहा। बैंक का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 1,628 करोड़ रुपए रहा था। एलआ कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 9,035 करोड़ रुपए हो गई, जो जनवरी-मार्च 2024 में 7,887 करोड़ रुपए थी।

इस दौरान ब्याज आय मामूली रूप से घटकर 6,979 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6,990 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में मुनाफा सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 7,515 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5,634 करोड़ रुपए रहा था। कुल आय बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 33,826 करोड़ रुपए हो गई, जो 2023-24 में 30,037 करोड़ रुपए थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में, बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 31 मार्च 2025 तक सकल अग्रिमों के 2.98 प्रतिशत तक कम हो गईं, जबकि 31 मार्च 2024 के अंत तक यह 4.53 प्रतिशत थी। शुद्ध एनपीए भी सालाना आधार पर 0.34 प्रतिशत से घटकर 0.15 प्रतिशत रह गया। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने 2.10 रुपए प्रति शेयर लाभांश का प्रस्ताव किया है। यह शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है।

केनरा एचएसबीसी लाइफ ने आईपीओ लाने सेबी के पास जमा किए दस्तावेज

बिक्री पेशकश के तहत केनरा बैंक 13.77 करोड़ शेयर बेचेगा

नई दिल्ली

रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) द्वारा सेबी के समक्ष आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल करने के कुछ दिन बाद केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। सेबी के समक्ष दस्तावेजों के अनुसार केनरा रोबेको एएमसी की तरह ही केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ प्रवर्तकों और एक निवेशक द्वारा 23.75 करोड़ शेयर की पूर्ण बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा। बिक्री पेशकश के तहत, केनरा बैंक 13.77 करोड़ शेयर बेचेगा, एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-पैसिफिक) होल्डिंग्स लिमिटेड 47.5 लाख शेयर बेचेगा और पंजाब नेशनल बैंक 9.5 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहा है।

आईपीओं के पूरी तरह ओएफएस होने के कारण कंपनी को सार्वजनिक निर्गम से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। इसके पास 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा एचएसबीसी समूह की एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स के पास 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

वर्ष 2024-25 में आधार कार्ड धारकों ने 2,707 करोड़ सत्यापन किए गए, अब तक हुए सत्यापन लेनदेन की कुल संख्या 14,800 करोड़ से अधिक हुई

नई दिल्ली। आधार कार्ड धारकों ने वित्त वर्ष 2024-25 में सत्यापन के लिए 2,707 करोड़ से अधिक लेनदेन किए जिनमें से 247 करोड़ सत्यापन अकेले मार्च महीने में ही किए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक मार्च 2025 में आधार के जरिये सत्यापन की कुल संख्या (246.75 करोड़) पिछले वर्ष की इसी अवधि के साथ फरवरी 2025 में किए गए सत्यापन से भी अधिक है। इसके साथ ही आधार की शुरुआत के बाद से अब तक हुए सत्यापन लेनदेन की कुल संख्या 14,800 करोड़ से अधिक हो गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित कृत्रिम मेधा/मशीन लर्निंग पर आधारित आधार चेहरा सत्यापन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल रही है।